मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

# मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

कोई 'जन-सेवक' चंदन नगर में एक रात सो कर दिखाए!! 2
खट्टर की बॉन्ड नीति के विरोध में मेडिकल छात्र उतरे संघर्ष पर 4
मज़दूर लेबर कोड्स का विरोध क्यों कर रहे हैं? 5
नोटबंदी को लेकर खुद अपराध बोध से ग्रस्त है मोदी सरकार 6
जानलेवा बनता जा रहा प्रदूषण 8

वर्ष 36 अंक 53 फरीदाबाद 13-19 नवम्बर 2022 फोन-8851091460 ₹ 5.00

# पुलिस द्वारा जारी दलालों की सूची में भाजपा नेताओं के नाम से हड़कंप

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** पुलिस महकमे से निकली दलालों की सूची सार्वजनिक होने के चलते भाजपा नेता अत्यधिक परेशान नज़र आ रहे हैं। सूची बनाने व इसे सार्वजनिक करने को लेकर शहर के एक बड़े नेता स्थानीय पुलिस अधिकारियों से काफ़ी ख़फ़ा हैं। जानकारों की माने तो इसे लेकर इनके बीच काफ़ी नोक-झोंक भी हुई है। मजे की बात तो यह है कि कोई भी पुलिस अधिकारी इस सूची के जारी तथा सार्वजनिक होने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा। इसे केवल अनाधिकृत रूप से लीक होना बताया जा रहा है।

गतांक में सुधी पाठकों ने पढ़ा होगा कि पुलिस महकमे द्वारा घोषित दलाल केवल दलाल ही नहीं हैं, वे अपना राजनीतिक प्रभाव भी इस्तेमाल करते हैं। अफसरों के तबादले एवं तैनातियां आदि करा कर उन पर भारी दबाव बना कर रखते हैं। इसके चलते कई बार पुलिस अफ़सरों को न चाहते हुए भी उल्टे-पुल्टे काम करने पड़ते हैं। ऊपर तक के अधिकारी भी, ऐसे में लाचारी व्यक्त कर देते हैं। जाहिर है कि इसके चलते जिले भर में गुन्डों एवं अपराधी गिरोहों के हौंसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप क्राइम

केन्द्र में भाजपा सरकार के मंत्री कृष्णपाल

काबू से बाहर होता जा रहा है।

महकमे के भरोसेमंद एवं उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो दलालों की यह सूची एक सोची-समझी रणनीति के तहत लीक करवाई गई है। राजनीतिक दबावों के चलते ऊंचे से ऊंचे स्तर के पुलिस अधिकारी इन राजनीतिक दलालों से पार पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। ऐसे में इन्हें सार्वजनिक तौर पर बेनकाब करके इन्हें कुछ हद तक नियंत्रित कर पाने की नीयत से यह सब किया गया है। भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने इस सूची को मीडिया में आने से रोकने के लिये भरसक प्रयास किये थे, जो काफ़ी हद तक सफल भी रहे।

इन दलालों द्वारा पुलिस पर बनाये जाने वाले दबाव की हकीकत समझने के लिये सात वर्ष पूर्व की एक घटना को याद करना जरूरी है। मामला 10 जून 2015 का है। मेवला महाराजपुर गांव के पचासों युवक जो अपने-आप को केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर के भाई-भतीजे आदि बताते थे, अपने शिकार का पीछा करते हुए ओल्ड फरीदाबाद के थाने में घुस आये थे। जिस व्यक्ति का वे शिकार करना चाहते थे। उसे पीसीआर गाड़ी ने जैसे-तैसे उनसे बचा कर थाने में घुसा दिया था।

लाठी-डंडों आदि से लैस बेखौफ़ भीड़ थाने में ऐसे घुसी चली आई जैसे कि थाना न होकर गांव की चौपाल हो। बीच-बचाव करने एवं उन्हें रोकने टोकने वाले पुलिसकर्मियों को भी इन युवकों ने नहीं बख्शा। तत्कालीन एसएचओ भारतेन्दु के साथ भी पूरी बदतमीजी एवं हाथा-पाई की। सूचना पाकर तत्कालीन डीसीपी सेन्ट्रल एवं क्राइम विजय प्रताप सिंह तुर्त-फुर्त भारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंच गये और जम कर उचित एवं वांछित कार्रवाई कर डाली।

यह सब मंत्री जी को कैसे सहन हो सकता था? उनके पैतृक गांव वालों के साथ पुलिस का यह व्यवहार भला वे कैसे पचा सकते थे? रात को ही तत्कालीन सीपी सुभाष यादव, डीसीपी व एसएचओ को मंत्री जी ने अपनी कोठी पर तलब कर लिया। घंटों मीटिंग चली, इसके बावजूद भी सुभाष यादव ने कड़ा स्टैंड लेते हुए दंगाइयों के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। कमजोरी लाल खट्टर की सरकार पर कृष्णपाल ने दबाव बना कर डीसीपी व एसएचओ का तबादला तो तुरंत करा दिया, लेकिन सीपी का नहीं करा पाया क्योंकि इस पर पुलिस महकमे ने कड़ा स्टैंड ले लिया था। तफ्तीश को अपने लोगों के हक में कराने के लिये केस को चंद घंटों के भीतर ही स्टेट क्राइम के हवाले करा दिया गया। इसके मुखिया उस वक्त मंत्री जी के सजातीय केपी सिंह होते थे। इसके परिणामस्वरूप किसी भी दोषी का कुछ नहीं बिगड़ सका।

इस घटना से जहां एक ओर पुलिस का मनोबल गिरता चला गया वहीं दूसरी ओर गुंडा एवं अपराधी गिरोहों की रफ्तार में वृद्धि होती चली गई। जहां-तहां जायदादों पर कब्जे तथा मार-पीट द्वारा डरा-धमका कर आम लोगों से वसूली के धंधे जोर पकड़ने लगे। इस श्रृंखला में बीते दिनों चेची नामक एक दलाल ने सेक्टर 28 की पुलिस चौकी में एक संभ्रांत व्यक्ति को बुला कर बुरी तरह से पीट कर उसके हाथ-पैर तोड़ दिये थे। नहर पार के ग्रेटर फरीदाबाद में तो इन गिरोहों की गुंडागर्दी एवं उठाइगिरी का तो खाता ही काफी लम्बा-चौड़ा है। सोसाइटियों में नये-नये बसे लोगों से ये लोग जम कर वसूली करते हैं। खुद ही सिक्योरिटी एवं मेन्टेनेंस के ठेके भी ले लेंगे, आरडब्लयूए पर अपना पूरा कब्जा रखेंगे, नहीं तो उन्हें मारे-पीटेंगे। इसी क्षेत्र की एक सोसाइटी के सक्रिय निवासी सेवानिवृत विंग कमांडर एवं वकील सतेन्द्र दुग्गल पर भी इन गुंडों ने कातिलाना हमला करने में कतई गुरेज नहीं किया। पुलिस बेशक तमाशाई बनी रहती है लेकिन लूट कमाई से अपना हिस्सा भी वसूलना नहीं छोड़ती।

उक्त सूची के प्रकाशित होने से और कुछ हो या न हो परन्तु जनता को एक बात तो स्पष्ट हो ही जानी चाहिये कि इन गुंडा गिरोहों का राजनीतिक गठजोड़ कितना मजबूत है।

# खट्टर ने राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ की जगह बिठाया भारत भूषण भारती को

**चंडीगढ़ ( म.मो. )** 9 नवम्बर को अजय गौड ने मुख्यमंत्री खट्टर के राजनीतिक सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया जिसे तुरन्त मंजूर कर लिया गया। इसकी जगह तुरन्त भारत भूषण भारती को नियुक्त कर दिया गया। संदर्भवश भारत के ये भूषण वही महापुरुष हैं जिन्होंने हरियाणा स्टाफ़ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन होते हुए हरियाणा सरकार की ऐसी फ़जीहत कराई थी कि सरकार को पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया था। उस समय इन्हें पद से हटा कर खट्टर ने राहत की सांस ली थी। समझा जा सकता है कि अक्ल से पैदल ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री को कैसी सलाह दे पायेगा। लगता है ऐसे ही सलाहकारों की बदौलत हरियाणा के शासन-प्रशासन का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है।

अब तक इस पद पर बने रहे अजय गौड़ की सलाहों का नजारा हरियाणा भर की जनता देख ही रही है। क्या अजय गौड अथवा भारती, खट्टर की अपेक्षा कहीं ज्यादा बड़े राजनीतिक वैज्ञानिक हैं जिनकी सलाह खट्टर के लिये आवश्यक होती है? मान ही लिया जाय कि आरएसएस के प्रचारक से मुख्यमंत्री बने खट्टर को राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है तो भी क्या उनका पूरा मंत्रीमंडल एवं विधायक दल इस लायक नहीं है कि जो इन्हें राजनीतिक

अजय गौड़, सीएम मनोहर लाल और भारत भूषण भारती

सलाह दे सके? इनके अलावा मुख्यमंत्री के पास एक से एक बेहतरीन, पढे-लिखे तथा कुशाग्र बुद्धिमान अफ़सरों की लम्बी-चौड़ी फ़ौज भी हैं। जरूरत केवल इतनी है कि खट्टर यह समझ सकें कि किससे क्या ज्ञान लेना है और किसको कहां इस्तेमाल करना है।

दरअसल भाजपा द्वारा अपने लगुए-भगुओं की सरकारी खर्च पर न केवल रोजी-रोटी बल्कि शाही ठाठ-बाठ का इन्तजाम करने की नीति के तहत इस तरह के अनेकों पद स्वीकृत किये गये हैं। कितने तो राजनीतिक सलाहकार, मीडिया एडवाइजर, दर्जनों चेयरमैन बना कर चंडीगढ़ में बैठा रखे हैं। इन्हें सरकारी आवास ड्राइवर सहित कार तथा शोभा बढ़ाने के लिये गन मैन दे रखे हैं। इनके दफ्तर व स्टाफ़ का खर्च तो अलग से है ही। इसी तरह का एक पाखंड सीएम वींडो का भी है। इस धंधे में भी कई संघियों को रोजगार मिला हुआ है। इनकी भीतरी जानकारी रखने वाले अनुभवी एवं भुक्तभोगी लोग, बताते हैं कि इन पदों पर आसीन लोग मुख्यमंत्री से अपनी निकटता के चलते खुल कर अपनी दुकानदारी चलाते हैं। इन्हें सत्ता के गलियारों में घूमते हुए प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए देखा जाता है। किसी को नियुक्ति, तबादला, सीएलयू किसी भी प्रकार का एनओसी तथा कोई भी अटकी हुई फ़ाइल निकलवाने के लिये इन्हें सर्वोत्तम दलाल समझा जाता है। कुल मिलाकर धंधा तो इनका दलाली का है और इन्हें ढोने का खर्चा गरीब कर दाता के सिर पर है।

ऐसा भी नहीं है कि ये उच्च पदस्थ सत्ता के दलाल सारी दलाली खुद ही डकार जायें। इनके जिम्मे पार्टी तथा संघ के लिये 'चंदा' एकत्र करने का कोटा भी होता है। इनके द्वारा पदों से दिये गये इस्तीफे केवल दिखावटी होते हैं। बीते दिनों किसी नौकरी घोटाले कि गुप्त बात लीक हो जाने पर ऐसे ही एक सलाहकार नीरज दफतुआर से भी इस्तीफ़ा तो ले लिया गया था लेकिन उनका धंधा ज्यों का त्यों बरकरार है।

अजय गौड सेक्टर 17 फरीदाबाद के रहने वाले हैं। वे यहां के जिला भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्ष 2019 में हुए विधानसभा के चुनावों में वे टिकट के उम्मीदवार थे। उम्मीदवार तो वे 2014 में भी थे परन्तु 2019 में उनका दावा काफी मजबूत था। इसे देखते हुए खट्टर ने उन्हें अपना बगलगीर बना कर एक प्रकार से सत्ता में हिस्सेदारी प्रदान कर दी। अब सवाल उठता है कि गौड के इस्तीफे की नौबत क्यों आई? जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है इस्तीफा केवल नाम-मात्र का दिखावा होता है बाकि सारा धंधा ज्यों का त्यों चलता रहता है। और तो और गनमैनों की टोली तथा गाड़ी-घोड़ा सब कुछ ज्यों का त्यों कायम रहता है।

राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक खट्टर उन्हें सक्रिय राजनीति में उतारना चाहते हैं। किसी भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री कभी नहीं चाहता कि राज्य के किसी क्षेत्र विशेष में कोई एक नेता उनसे भी भारी हो जाय। इसलिये हमेशा सत्ता संतुलन बनाये रखने के लिये किसी न किसी एक नेता को उभारने का प्रयास करता है। फरीदाबाद क्षेत्र में कृष्णपाल गूजर का राजनीतिक कद जरूरत से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वे यहां के मुख्यमंत्री सरीखे हो चुके हैं। उन्हें संतुलित करने के लिये खट्टर ने पहले विपुल को उभारने का प्रयास किया था, लेकिन विपुल समय से पहले ही पंचर हो गये। अब गौड पर दाव खेला जा रहा है। सम्भावना जतायी जा रही है कि नगर निगम के मेयर पद के लिये गौड या उनकी पत्नी को खड़ा किया जाय। विदित है कि कृष्णपाल भी इस पद के लिये अपने बेटे को तैयार करने में जुटे हुए हैं, जिसे खट्टर कभी स्वीकार करने वाले नहीं हैं।